एक देश, एक चुनाव

वर्तमान संदर्भ

- केंद्र सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' की संभावना तलाशने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

विवरण

- वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था।
- यह कदम लोकसभा चुनाव के बाद और उसके साथ होने वाले आम चुनावों और कुछ राज्य के विधानसभा चुनावों को तय समय से पहले कराने का संकेत देता है।
- इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद मई-जून, 2024 में लोकसभा चुनाव भी संपन्न कराए जाएँगे।

एक साथ चुनाव

आशय

- यह भारतीय चुनाव चक्र की संशोधित संरचना है, जहां संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव को समकालिक करते हुए एक साथ चुनाव सम्पन्न कराए जाएँगे।
- मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालने में सक्षम होंगे।

इतिहास

- वर्ष 1952 और वर्ष 1957 में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हुए थे।
- सामान्यत: भारत में वर्ष 1967 तक यह दौर जारी रहा परन्तु वर्ष 1959 में केवल केरल राज्य में यह क्रम टूट गया और वहां के विधानसभा के चुनाव समय से पूर्व कराए गए।
- वर्ष 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया।
- वर्ष 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया गया।
- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर गठित संसद की स्थायी समिति द्वारा वर्ष 2015 में 'एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता' पर एक रिपोर्ट तैयार की गई।
- संवैधानिक पृष्ठभूमि : एक साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए संविधान के कम से कम निम्न पाँच अनुच्छेदों में संशोधन करना आवश्यक होगा:
- अनुच्छेद 83 : संसद के सदनों की अवधि।
- अनुच्छेद 85 : संसद के सत्र एवं उनका ष्अवसान और विघटनष।
- अनुच्छेद 172 : राज्य विधानसभाओं की अवधि।
- अनुच्छेद 174 : सदन को स्थगित करने या विधानसभा को भंग करने की राज्यपाल की शक्ति।
- अनुच्छेद 356 : किसी राज्य में ष्राष्ट्रपति शासनष लगाना।

एक साथ चुनाव कराने के लाभ

- विधि आयोग (2018) द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि एक साथ चुनाव संपन्न होने से निम्नलिखित लाभ होंगे:
- सार्वजनिक धन की बचत।
- प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा बलों पर कम बोझ।
- नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन का सुनिश्चित होना।
- प्रशासनिक तंत्र का निर्वाचन कार्यों के बजाय विकासात्मक गतिविधियों में संलग्न रहना।

चुनावी लागत में कमी

- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपये का भारी खर्च हुआ, जिसमें चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया खर्च भी शामिल है।
- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर गठित संसदीय स्थायी समिति (2015) ने बताया कि वीवीपैट मशीनों की बड़े पैमाने पर खरीद के लिए कुल 9,284.15 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
- प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि : अलग-अलग समय पर चुनावों से सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य प्रभावित होते हैं, क्योंकि अधिकारी मतदान कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निरंतर बाधा उत्पन्न होती है।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश : यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने का एक साधन हो सकता है।

एक साथ चुनाव कराने के नुकसान

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

- वर्ष 2018 में विधि आयोग ने दावा किया कि मौजूदा संवैधानिक संरचना के अंतर्गत एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं।

क्षेत्रवाद की भावना

- क्षेत्रीय दल अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में आ सकते हैं।
- ऐसा होने से क्षेत्रीय दल चुनावी खर्च और रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय दलों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

संघवाद के समक्ष चुनौतियाँ

- आईडीएफसी संस्थान अध्ययन, 2015 के अनुसार एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक ही जीतने वाले राजनीतिक दल/गठबंधन को चुने जाने की संभावना 77 प्रतिशत है ।
- एक साथ चुनाव होने पर बहुसंख्यक केंद्र सरकार के कारण गैर-सहयोगी राज्यों के निष्प्रभावी हो जाने की आशंका है।
- अपनी चुनाव तिथियों को एक समान बनाने के लिए मौजूदा राज्य विधानसभाओं की शर्तों को मनमाने ढंग से कम करने/बढ़ाने को राज्यों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किए जाने की संभावना है।
- सरकार की जवाबदेही : बार-बार चुनाव, चुने हुए प्रतिनिधियों को सक्रिय रखते हैं और लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ाते हैं।
- हिंसा की प्रवृत्ति : चुनाव में हाल के दिनों में हिंसात्मक घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ और अधिक जोखिम में वृद्धि हो सकती है।

संचालन चुनौतियाँ

- ईवीएम की व्यवस्था : एक साथ चुनाव कराने के लिए करीब 30 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी। 6-7 लाख ईवीएम बनाने में लगभग एक साल का समय लगा था। ईवीएम की अपेक्षित संख्या को देखते हुए यह काम बेहद मुश्किल है।
- केंद्रीय बलों, चुनाव कर्मचारियों की तैनाती : ड्यूटी के घंटों के विस्तार, शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों आदि पर विचार करते हुए पर्याप्त पारिश्रमिक सुनिश्चित करने सहित सुरक्षा बलों और चुनाव कर्मचारियों की अचानक अतिरिक्त जरूरत होने से इन बलों के संतुलित आवंटन में समस्या उत्पन्न हो सकती है।

चुनाव संचालन संबंधी चुनौतियों को कम करने के उपाय

- निर्वाचन आयोग को अनुपूरक संसाधन आवंटित किए जा सकते हैं।
- ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के तेजी से निर्माण हेतु अधिक संस्थानों को लाइसेंस दिया जाना चाहिए।
- कार्यान्वयन में तालमेल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन अधिकारियों की एकीकृत कार्यप्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- एक साथ चुनाव संपन्न कराने का निहितार्थ केवल एक मतदान प्रक्रिया ही नहीं है बल्कि एक स्थिर शासन व्यवस्था भी है। इस तरह के संवेदनशील और दूरगामी सुधार के लिए सभी हितधारकों के सर्वसम्मत समर्थन की आवश्यकता है।
- निर्वाचन आयोग की तत्परता, मतदाताओं की स्वीकृति और नीति पर आम सहमति बनाने के प्रयास हेतु अन्य प्रासंगिक कारकों के संदर्भ में इस कदम की व्यवहार्यता का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश

- हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम, ट्रांस-पॅसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (CPTPP) में शामिल हो गया है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- इसके लिए न्ज्ञ और ब्व्ज्च्च देशों के मध्य लगभग 21 महीने से बातचीत चल रही थी और अब न्ज्ञ ने इस समझौते पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर कर दिया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- इस समझौते को मूल रूप से वर्ष 2005 में ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे।
- हालांकि, अमेरिका वर्ष 2017 में इस समझौते से बाहर हो गया, शेष 11 देशों को इस समझौते को फिर से नया करना पड़ा और लागू किया गया और तब से इस समझौते को CPTPP नाम से जाना जाता है।

CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans&Pacific Partnership) के बारे में;

- CPTPP 11 देशों के मध्य किया गया एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।
- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली।
- CPTPP पर 8 मार्च 2018 को सैंटियागो (चिली) में हस्ताक्षर किए गए थे।
- हाल ही में ब्रिटेन के शामिल होने के निर्णय के बाद से CPTPP में कुल 12 सदस्य हो जाएंगे।
- CPTPP विश्व स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है।

- जो वर्ष 2021 में वैश्विक GDP के 12% (£11 ट्रिलियन) की हिस्सेदारी शामिल है, यूके के प्रवेश के साथ यह 15% तक बढ़ सकता है।
- यूके इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है।

यूके के शामिल होने के लाभ

- CPTPP सदस्यों को यूके के 99% से अधिक निर्यात के लिए टेरिफ मुक्त व्यापार उपलब्ध होने की उम्मीद है।
- UK की सदस्यता CPTPP देशों को ळक्च् के हिसाब से दुनिया के छठवें सबसे बड़े बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करेगी।
- CPTPP में यूके की सदस्यता चिली, मैक्सिको और पेरू सहित मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का पूरक होगी।
- CPTPP में यूके के प्रवेश से सभी सदस्य देशों के व्यवसायों और निवेशकों के लिए कई संभावित लाभ हैं।
- यह समझौता न्ज्ञ में निवेश स्थापित करना और संचालित करना आसान बना देगा।
- एक स्वतंत्र व्यापारिक राष्ट्र के रूप में UK, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करना जारी रखेगा और साथ ही संरक्षणवाद और व्यापार की बाधाओं को दूर करेगा।

CPTPP के प्रमुख व्यापार उद्देश्य

- CPTPP को टैरिफ कम करने और इसके सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले 95% से अधिक सामानों पर टैरिफ को समाप्त करना और सेवाओं और निवेश के लिए अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना है।
- इस समझौते में बौद्धिक संपदा, श्रम और पर्यावरण मानकों पर प्रावधान भी शामिल हैं।

ब्रिटेन CPTPP के साथ कितना व्यापार करता है?

- सितंबर 2022 तक पिछले बारह महीनों में CPTPP देशों को ब्रिटिश निर्यात 60.5 बिलियन पाउंड का था।
- समूह की सदस्यता दीर्घावधि में प्रत्येक वर्ष 1.8 बिलियन पाउंड और जोड़ेगी और यदि अन्य देश इसमें शामिल होते हैं तो संभवत: और भी अधिक हो सकती है।

भू राजनीतिक विचार: चीन फैक्टर

- इस समझौता से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक लाभ होना तय है, लेकिन ब्रिटेन के पास इस समझौते में शामिल होने के अन्य कारण भी हैं।
- जैसे चीन इस संधि में शामिल होता है या नहीं, इस पर ब्रिटेन को वीटो मिल जाएगा।
- बीजिंग ने सितंबर 2021 में इस समझौते का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है ।

वनवेब इंडिया-2 मिशन

सन्दर्भ

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा वनवेब इंडिया-2 मिशन के अंतर्गत LVM3 प्रक्षेपण रॉकेट से वनवेब के 36 उपग्रहों को निम्न-भू कक्षा में स्थापित किया गया।

वनवेब

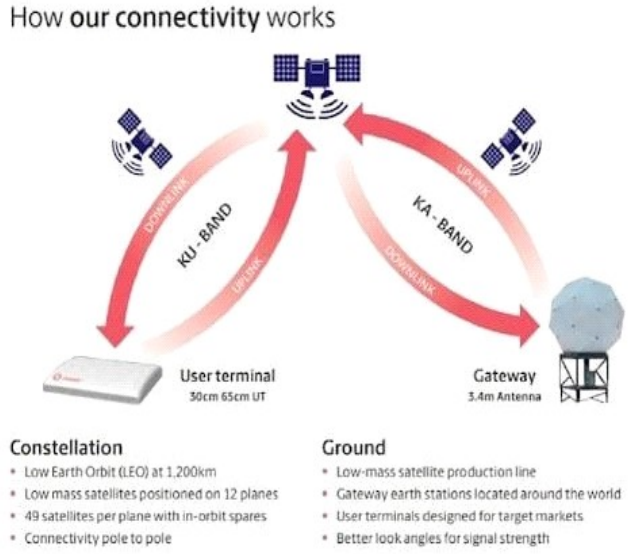

- वनवेब एक वैश्विक संचार नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट प्रदान करना है।
- यह सरकारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है।
- NSIL (इसरो की वाणिज्यिक शाखा) ने वनवेब के साथ 72 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे।
- इस अनुबंध के हिस्से के रूप में, 36 संचार उपग्रहों को वनवेब इंडिया-1 मिशन के तहत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्टड3 प्रक्षेपण यान द्वारा 23 अक्तूबर, 2022 को कक्षा में स्थापित किया गया था।

प्रक्षेपण यान एलवीएम3 (LVM3) या जीएसएलवी-एमके3

- LVM3 रॉकेट, को भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान माना जाता है, इसे पहले GSLV-Mk3 के नाम से जाना जाता था।
- LVM3, इसरो द्वारा विकसित, तीन चरणों वाला भारी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है।

- LVM3 में शामिल हैं -
- ठोस ईंधन जलाने में मदद करने वाली दो ठोस स्ट्रैप-ऑन मोटरें।
- एक कोर-स्टेज तरल बूस्टर, जो तरल ईंधन के संयोजन को जलाता है।
- C25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, जो तरल ऑक्सीजन के साथ तरल हाइड्रोजन को जलाने में मदद करता है।
- LVM3 रॉकेट को 4 टन वर्ग के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) और लगभग 8 टन के उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में ले जाने के लिए विकसित किया गया है।

AUKUS समझौता

संदर्भ

- हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते 'ऑकस' (AUKUS) के तहत पांच अमेरिकी परमाणु-संचालित पनडुब्बियों को खरीदने की घोषणा की है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- इसके अंतर्गत अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा निर्मित परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया को सौपा जाएगा।
- इस समझौते को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समझौते की विशेषता

- क्वाड की धारणा के विपरीत यह गठबंधन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्पष्ट रूप से घोषित सैन्य गठबंधन है।
- इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों के रणनीतिक हितों की रक्षा करना है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियाँ वैश्विक समुदाय के लिये चिंता का विषय हैं।
- यह समझौता ऑस्ट्रेलिया एवं चीन के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जो पहले से ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ध्यातव्य है कि चीन ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। वर्तमान में दोनों देशों के मध्य लगभग 200 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है।

महत्त्व

- यह कदम इंडो-पैसिफिक में स्थिरता को बढ़ावा देगा और साझा मूल्यों और हितों का समर्थन करेगा।
- यह एक शांतिपूर्ण और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

परमाणु ऊर्जा सम्पन्न पनडुब्बी का महत्त्व

- परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को लंबी अवधि के लिए तैनात किया जा सकता है और कम बार सतह पर आने की जरूरत होती है।

समझौते के प्रति चीन का दृष्टिकोण

- चीन ने इस समझौते के प्रति चिंता व्यक्त की है। उसका मानना है कि इस प्रकार के समझौते उसे केंद्र में रखकर तथा उसके हितों को प्रभावित करने के लिये किये जा रहे हैं।
- चीन ने ऐसे समझौतों को क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिये खतरा तथा हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने वाला माना है।
- गौरतलब है कि चीन के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियाँ हैं। इनमें परमाणु मिसाइलों को भी लॉन्च करने की क्षमता है। 'ऑकस' समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियाँ प्राप्त होने के बाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी नौसैनिक क्षमता में वृद्धि होगी।

भारत पर प्रभाव

- हालांकि भारत AUKUS समूह का सदस्य नहीं है AUKUS के प्रति कथित उदासीनता के बावजूद, भारत AUKUS व्यवस्था से लाभ प्राप्त कर सकता है
- जैसे चीन द्वारा श्घेरे की नीतिश के संबंध में भारत की चिंताओं को AUKUS द्वारा आंशिक रूप से कम किया जा सकता है।
- हालांकि बात की आशंका है कि इस सौदे से अंतत: पूर्वी हिंद महासागर में परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों की भीड़ हो सकती है, जिससे भारत की क्षेत्रीय श्रेष्ठता का क्षरण हो सकता है।

भारत में परमाणु संचालित पनडुब्बी

- भारत विश्व के उन छह देशों में शामिल है, जिनके पास परमाणु संचालित पनडुब्बियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस तथा चीन के पास भी ऐसी पनडुब्बियाँ हैं।
- भारत ने वर्ष 1987 में सोवियत संघ से k-43 चार्ली क्लास परमाणु स्वचालित पनडुब्बी प्राप्त की थी। भारतीय नौसेना में इसे आईएनएस चक्र नाम दिया गया। इसने वर्ष 1991 तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएँ दी थी।
- भारत ने रूस से वर्ष 2012 में एक और परमाणु संचालित पनडुब्बी को लीज पर लिया था। इसे नौसेना में आईएनएस चक्र 2 नाम दिया गया।
- आईएनएस अरिहंत परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। इसका जलावतरण जुलाई 2009 में किया गया था। वर्ष 2018 में परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद इसे रणनीतिक सहायक नयूक्लियर सबमरीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- आईएनएस अरिहंत भारत के परमाणु त्रय को पूरा करती है अर्थात देश को जमीन, विमान और पनडुब्बी से परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता प्राप्त है।
- आईएनएस अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को भी जल्द ही नौसेना में शामिल किये जाने की संभावना है।

ग्रेट निकोबार परियोजना

सुर्खियों में क्यों ?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के निर्माण को लेकर पर्यावरणीय चिंता प्रकट की जा रही है।

प्रमुख बिन्दु

- जनवरी 2023 में संवैधानिक आचरण समूह जिसमें लगभग 100 पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग की थी ।

परियोजना का संचालन - नीति आयोग

- नोडल एजेंसी - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)
- इस परियोजना पर होने वाला अनुमानित व्यय लगभग 72,000 करोड़ रुपए है।

निकोबार परियोजना

उद्देश्य

- ग्रेटर निकोबार के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
- इस परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र तथा एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है।
- इसके अलावा, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में एक लाख पेड़ों को काटकर बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

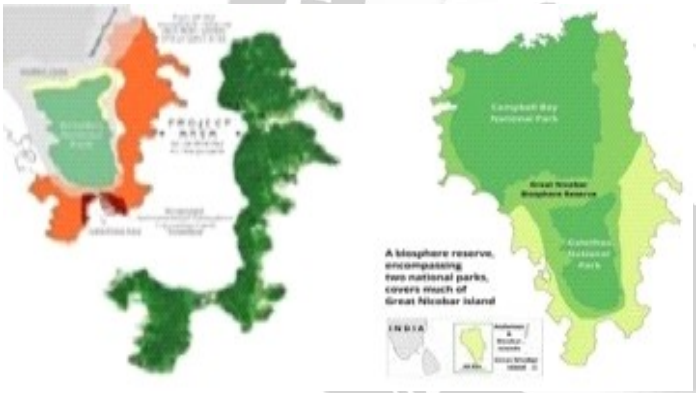

- इस योजना के अंतर्गत, बायोस्फीयर रिजर्व की सीमाओं के भीतर कुल 244 वर्ग किमी हरे-भरे जंगल और तटीय क्षेत्रों का उपयोग शामिल है।
- परियोजना क्षेत्र गैलाथिया बे नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क के 10 किमी के दायरे में आता है।
- हालांकि, यह राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास अधिसूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के बाहर स्थित है।
- नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) की स्थायी समिति ने, बंदरगाह और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूरे गैलाथिया बे वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित कर दिया।

निकोबार परियोजना से जुड़ी चिंताएं

- इस परियोजना के लिए प्राचीन वर्षावनों में लाखों पेड़ काटे जाएंगे तथा लगभग 12 से 20 हेक्टेयर मैंग्रोव कवर का विनाश होगा।
- लगभग 10 हेक्टेयर प्रवाल आवरण प्रभावित हो सकते हैं।
- स्थानीय शोम्पेन और निकोबारी जनजाति के मूल निवासी प्रभावित होंगे।
- लेदरबैक समुद्री कछुए, निकोबार मेगापोड(निकोबार द्वीपसमूह का एक उड़ान रहित पक्षी), निकोबार मकाक और खारे पानी के मगरमच्छ जैसे कुछ दुर्लभ जीव भी इस परियोजना से प्रभावित होंगे।

निकोबार परियोजना का महत्त्व

- योजना में बुनियादी ढांचे (बंदरगाह, हवाई अड्डे, आदि) का निर्माण शामिल है, इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
- इससे क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं पैदा करने में मदद मिलेगी, जिससे आय सृजन में वृद्धि होगी।
- विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास से, अंतर-द्वीप कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- यह स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और पर्याप्त वायु, समुद्र और वेब बुनियादी ढांचे के लिए सस्ती अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण करेगा।
- निकोबार द्वीप, मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित है, यह क्षेत्र में भू-राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण की मांग करता है।
- इस द्वीप में, भारत की एकमात्र त्रि-सेवा कमान (अंडमान एवं निकोबार कमान) भी स्थित है।

सुरक्षात्मक उपाय

- पर्यावरण समिति ने अधिकारियों को जंगल और समुद्र के किनारे को जोड़ने वाले आठ स्थानों पर वन्यजीव गलियारे बनाने का निर्देश दिया है।
- स्वदेशी समुदायों पर प्रभाव की संभावना की निगरानी के लिए शीर्ष स्तर की सुविधाओं के साथ एक विशेष इकाई स्थापित की जाएगी।
- पेड़ों के भीतर रहने वाली प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों की कटाई चरणबद्ध तरीके से की जानी चाहिए।
- परियोजना से उत्पन्न कचरे का या तो पुनर्नवीनीकरण और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए, या सुरक्षित निपटान के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से मुख्य भूमि तक सावधानी से ले जाया जाना चाहिए।

ooo

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR